

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2539
16.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

हरियाणा में फेम के अंतर्गत ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना

2539. श्री जय प्रकाश:

श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या क्रमशः हिसार और सोनीपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में 'फेम' (इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण) स्कीम के अंतर्गत मौजूदा ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या और ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत कम/धीमी है;
- (ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में अब तक कितने सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्वीकृति प्रदान की गई है और उनमें से वास्तव में कितने कार्य कर रहे हैं;
- (ग) क्या शहरी और ग्रामीण मार्गों पर चार्जिंग नेटवर्क की कमी के कारण ई-वाहनों के उपयोग में बाधा आ रही है और क्या इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करने के लिए हरियाणा सरकार के समन्वय से कोई रूपरेखा तैयार की गई है;
- (घ) क्या सरकार ने चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए कोई प्रोत्साहन नीति, वित्तीय सहायता या प्रायोगिक परियोजना तैयार की है;
- (ङ) क्या हिसार को हरियाणा का क्षेत्रीय इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग केन्द्र बनाने और भविष्य में सोनीपत को इलेक्ट्रिक वाहन हितेषी क्षेत्र बनाने के लिए कोई ठोस कार्य-योजना है; और
- (च) क्या नगर परिषद और राजमार्ग क्षेत्रों में भूमि आवंटन और बिजली कनेक्शन की कमी के कारण परियोजनाएं रुकी हुई हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने फेम-II स्कीम के तहत हिसार में 45 ईवीपीसीएस और सोनीपत में 22 ईवीपीसीएस स्थापित किए हैं, जिनमें से हिसार में 36 ईवीपीसीएस और सोनीपत में सभी 15 ईवीपीसीएस चालू हो चुके हैं।

ज़िला	फेम-II के अंतर्गत स्थापित ईवीपीसीएस की संख्या	फेम-II के अंतर्गत प्रचालित ईवीपीसीएस की संख्या
हिसार	45	36
सोनीपत	22	15
कुल	67	51

(ग): भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा अभी तक ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है।

(घ): विद्युत मंत्रालय ने 17.09.2024 को "इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश-2024" जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विस्तार में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भूमिका पर जोर देते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (ईवीसीएस) स्थापित करना एक गैर-लाइसेंस प्राप्त गतिविधि है और निजी संस्थाएं पूरे भारत में ईवीसीएस स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ङ): फिलहाल एमएचआई की ऐसी कोई योजना नहीं है। हालांकि, एमएचआई ने पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत अखिल भारतीय स्तर पर ईवीपीसीएस की स्थापना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया है।

(च): तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, फेम-II के तहत हिसार और सोनीपत में ओएमसी द्वारा स्थापित 67 ईवीपीसीएस में से 16 ईवीपीसीएस को अभी तक विद्युत कनेक्शन की अनुपलब्धता के कारण चालू नहीं किया गया है।
